

नेबुआ नौरंगिया पुलिस ने चोरी गए ऑटो के साथ दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

नेबुआ नौरंगिया, कश्मीरमराजपुर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नेबुआ नौरंगिया थाना पुलिस ने चोरी की घटना को सफल अनाकरण करते हुए चोरी गए एक ऑटो (टैपे) को बरामद कर दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, थाना नेबुआ नौरंगिया में पंजीकृत मुकदमा संख्या 258/2026 को विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने चोरी गए PLAGGIO ऑटो (वाहन संख्या यूपी53DT7831) को बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने सुरज सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह निवासी नौरंगिया खास, थाना नेबुआ नौरंगिया तथा राजन पुत्र उमेश निवासी पथलहा वाई नंबर-14 मस्जिदिया टोला, थाना हनुमानगंज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

रिपब्लिकन
मजदूर संगठन
के सदस्य बनें

E-mail :
rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती ग्रन्थ
वॉ-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

छात्रों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने रोका; शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक पर सरकार को घेरा

नई दिल्ली। (ए.के.चौधरी) दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, लगातार हो रहे पेपर लीक और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि देश के लाखों छात्रों का भविष्य पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की खामियों के कारण प्रभावित हुआ है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार जवाबदेही तय करने के



बजाय विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर

रही है। कांग्रेस के अनुसार, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के आह्वान पर मुख्यालय की ओर कार्यकर्ता भाजपा शांतिपूर्ण मार्च कर छात्रों के पक्ष में अपनी आवाज उठाने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस ने कहा कि वह छात्रों के हितों की रक्षा और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेगी। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की भी मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता और शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार नहीं किए जाते। छात्रा-सहित गौड़

ममटेजपुर में विकास की तस्वीर देख जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने की कार्यों की सराहना

अम्बेडकरनगर। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बुधवार को विकासखंड टांडा के ग्राम ममटेजपुर में अमृत सरोवर सहित विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत सरोवर की गुणवत्ता एवं रखरखाव का जायजा लेकर किए गए कार्यों पर संतोष व्यक्त किया और संबंधित अधिकारियों को सराहना की। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया। अभियान जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और वृक्षरोपण से पर्यावरण संतुलन के साथ आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। उन्होंने ग्रामीणों से अधिकाधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। निरीक्षण के दौरान डीसी मनरेगा अनुप सिंह, खंड विकास अधिकारी राधेवंद प्रताप सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

तहसीलदार गरिमा मार्गत ने महापंचायत में सुनीं शिकायतें, दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

अम्बेडकरनगर। प्रदेश शासन के निर्देश पर हंसवर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत जैनुचैनपुर स्थित पंचायत भवन में बुधवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में तहसीलदार गरिमा भार्गव तथा सय नारायण गौड़ ने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। महापंचायत के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, पेयजल, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवस्य योजना, राशन कार्ड, विधुत, पेयजल तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया। तहसीलदार गरिमा भार्गव ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पत्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध ढंग से मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनशिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। महापंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

डीसीएम से मिला प्रतिनिधि मंडल, उर्स स्पेशल ट्रेने चलाने तथा जायरीनों की सुरक्षा व सुविधा की मांग

बरेली। उर्स-ए-रजवी के संबद्ध में आज दरगाह प्रमुख इब्राहिम मौलाना सुब्बान रजा खान (मुहम्मदी गिया) व सन्तानदासीन मुफ्ती अहमद मिर्जा की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल डीसीएम मुरादाबाद महेश यादव से मिला। दरगाह प्रमुख की ओर से मुरादाबाद गए प्रतिनिधि मंडल में शाहिद खान नुरी, परवेज नुरी व अजमल नुरी के नेतृत्व में डीआरएम को ज्ञापन रोपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि विश्व विख्यात उर्स-ए-रजवी का इस वर्ष 108 वां उर्स 06.07.08 अगस्त को बड़े धूमधाम से बरेली में मनाया जाएगा। विभिन्न देश के विभिन्न प्रदेशों से असीमित संख्या में रेल मार्ग द्वारा बरेली आते हैं। बाहर से आने वाले यात्रीनों की सुविधा के लिए बरेली की ओर सभी दिशाओं में उर्स स्पेशल ट्रेन चलाने, उर्स के दौरान बरेली से गुजरने वाली सभी अप-डउन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने, उर्स स्पेशल पर टिकट विंडो खोलने व समय सारिणी लगाने तथा बरेली के सभी स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट विंडो और साफ-सफाई पानी की व्यवस्था करने के अलावा ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ाकर रखने की मांग की। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि डीसीएम महेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल को आवश्यक किया कि रेलवे उर्स पर पिछले साल से बेहतर इस बार व्यवस्था करेगा। दरगाह की ओर से गत दिवस रेल मंत्री को भी पत्र लिखकर स्पेशल ट्रेने चलाने के साथ यात्रीनों की सुरक्षा व सुविधा की मांग की जा चुकी है। तथा उर्स की व्यवस्थाओं को लेकर एक पत्र डीआरएम को भी भेजा जा चुका है।

भाजपा बृथ अध्यक्ष संगठन की सबसे मजबूत कड़ी : सुभाष भटनागर

मुरादाबाद। रामपुर रोड स्थित एचबी क्लबाइड, जोरो पॉइंट पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुंदरकी विधानसभा का बृथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि एवं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष भटनागर ने कहा कि बृथ अध्यक्ष केवल संगठन का दायित्व नहीं निभाते, बल्कि पार्टी की विजय यात्रा के सबसे मजबूत आधार स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बृथ पर सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता ही जनता के विश्वास को जीत में बदलते हैं। कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में जनसेवा, सुराशन और विकास के संकल्प को बृथ स्तर तक पहुंचाना सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने घर-घर जाकर केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। सम्मेलन में विधायक ठाकुर रामवीर सिंह और मुख्य अतिथि सुभाष भटनागर ने सभी बृथ अध्यक्षों को प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया तथा सड़क अग्रगण्य के प्रति जागरूकता के लिए हेल्मेट वितरित किए। इसके अलावा नोट उठो कर एम्बोबीएस में चर्चित कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में सदस्यता अभियान, सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार तथा आगामी चुनावों की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन में जिला उपाध्यक्ष चंद्रपाल सैनी, जिला उपाध्यक्ष अशोक प्रजापति, जिला मंत्री ज्योति वाल्मीकि, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सैनी, नीरज चंदा, बबलू जादव, संजय कश्यप सहित सभी पार्टी पदाधिकारी एवं बृथ अध्यक्ष उपस्थित रहे।

ई-रिवशा चालक के बेटे ने नीट यूजी पास कर एमबीबीएस में बनाई जगह



विलारी।

क्षेत्र के ग्राम सफ़ीपुर निवासी ई-रिवशा चालक छत्रपाल सिंह जादव के पुत्र अरवि कुमार ने नीट यूजी परीक्षा उत्तीर्ण कर एम्बोबीएस में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया है। उनकी सफलता से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। 17 जुलाई को घोषित परिणाम में अरवि कुमार ने 720 में से 496 अंक प्राप्त किए। उन्हें ऑल इंडिया रैंक 95,689 तथा केंद्रेय रैंक 4,022 मिली, जिसके आधार पर उनका एम्बोबीएस के लिए चयन हुआ है। अरवि कुमार ने बताया कि उनके दिवंगत पिता स्व. लाखन सिंह का सपना था कि उनका पेटा डॉक्टर बने। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के सहयोग और कठिन परिश्रम को दिया। अरवि कुमार ने स्नातकोत्तर एवं इंटरमीडिएट की शिक्षा डी पीएल स्कूल से प्राप्त की है। इस उपलब्धि पर भीम आर्मी एवं आनंद समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल सचिव एडवोकेट सतीश कुमार ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कराएगा व्यापारी सम्मेलन

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों के साथ लगवाएगा कैंप



फतेहपुर।

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल फतेहपुर की मासिक बैठक चैक स्थित केप कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला प्रभारी संजय गुप्त और संरक्षक विनोद गुप्त ने एकमत होकर बैठक को अग्रगत करवा कि अतिरिक्त में जनपद में विधानसभावार व्यापारी सम्मेलन

या स्वर्णकारों के व्यापार के सम्बन्ध में बात करेगा तो उसके खिलाफ बाजार का एक प्रतिनिधि मंडल उच्च अधिकारियों से इसकी शिक्षाप्रद करेगा और उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करवाई जाएगी। जिला अध्यक्ष बुजेंद्र सैनी ने कहा कि जनपद के अधिक से अधिक व्यापारियों को हेन में पंजीकरण करवाने में जागरूकता की कमी है, इसके लिए प्रेरित किया जाएगा और तहसील स्तर में हेन विभाग के कैम लगवाए जाएंगे, जिससे प्रदेश सरकार का राजस्व बढ़े और व्यापारियों को 10 लाख रुपये दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिल सके। बैठक में राधेश्याम हथराण, धर्मेन्द्र गुप्ता, शैलेंद्र शरण, बसपा नेता मो. आशिफ एडवोकेट, संजय जौरी, विकास गुप्ता, बसपा नेता धीरज बल्लोकि, तोपू सिंह, रवि गुप्ता, अर्पित रस्तोगी, मो. अलीम, गुड मोहनवाल, सुरेंद्र वर्मा, मो. अनोस, मोनू गुप्ता, प्रदीप कश्यप, डा. रामू गुप्ता, मो. अमीर, मो. मुकीम, सोनू गुप्ता आदि व्यापारी मौजूद रहे।



595720 गोवर्धनी एवं महिषवर्णीय पशुओं का एफएमओडी0कारण किया जायेगा। जनपद के समस्त ग्रामी में चर माह से अधिक आयु के गोवर्धनी एवं महिषवर्णीय पशुओं का शतप्रतिशत टीकाकरण किया जायेगा तथा पशुओं की ईयर टैगिंग भी अनिवार्य रूप से की जाएगी। टीकाकरण के दौरान सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारी, मैत्री और पैगवेट द्वारा भारत पशुधन ऐप पर टीकाकरण की रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन फीडिंग की जायेगी। इसमें पशुओं का टैग नंबर और पशुपालक का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पशु का पुरा विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। आन लखन फीडिंग के समय पशुपालक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी भेजा जायेगा जिसके लिए पशुपालक से अनुरोध है कि टीकाकरण के समय प्राप्त ओटीपी0 को टीकाकरणकर्ता से साझा करें जिससे टीकाकरण का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज किया जा सके। कोल्ड चैन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण किया जाएगा। जिन पशुओं को फ्लू बी टी टीका लगवाया जा रहा है, उन्हें एक माह बाद बूस्टर डोज भी दी जाएगी। विकास खंड अंतर्गत गोशालाओं में भी प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण कराया जाएगा। एफएमओडी0 बीमारी के कारण पशुओं के मुंह एवं पैरों में छले, बुखार, कमजोरी, दुग्ध उत्पादन में गिरावट आती है। इस रोग के कारण भारत का दुग्ध उत्पादक देश होते हुए भी वैश्विक बाजार में पशुधन उत्पादों के निर्यात में बाधा आती है। इस बीमारी का उन्मूलन राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। अभियान के दौरान टीकाकरण की टीमें गांव / शहरों की हर गली और हर खूंट तक पहुंचेंगी। विभाग का लक्ष्य शत-प्रतिशत पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित करना है, ताकि जनपद के पशुओं की संरक्षक बीमारी से पूरी तरह बचाया जा सके। अस्तु जनपद के समस्त पशुपालकों से अनुरोध है कि पशुपालन विभाग की टीकाकरण टीम के ग्राम में आने पर पशुओं को एफएमओडी0 से बचाव हेतु अपने अपने पशुओं को टीका लगवाने एवं पशुओं की टैगिंग करने में सहयोग करें तथा अपने पशुओं को रोग मुक्त रखें।

बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम, पार्टी नेताओं से की मुलाकात, 37 योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड होगा पेश, सुस्त अफसरों की आज लगेगी क्लास



बरेली। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोदी बुधवार को बरेली पहुंच गए। बैठक को लेकर प्रशासनिक प्रतीति की समीक्षा करेंगे। बैठक को लेकर प्रशासनिक अमले में सुधार से हो लक्ष्य रखें और सभी विभाग अपने-अपने आंकड़ों के साथ तैयार नजर आए। डिप्टी सीएम की समीक्षा बैठक में वर्ष 2017 से अब तक संचालित 37 प्रमुख योजनाओं की प्रगति, बजट व्यय और लाभार्थियों का पूरा नंबर रखा जाएगा। अधिकारियों को योजनाओं की वित्तिय और शौकिक प्रगति के अद्यतन आंकड़ों के साथ प्रस्तुत होने के निर्देश दिए गए हैं। कई विभागों ने देर रात तक रिपोर्टों को अंतिम रूप देकर लाभार्थियों और बजट व्ययों का मिलान किया।

अधुरी परियोजनाओं पर होगी सीधी जवाबदेही सुर्जों के मुताबिक, बैठक में उन परियोजनाओं को भी समीक्षा होगी जो तय समय सीमा के बावजूद पूरी नहीं हो सकीं। लक्ष्य से पीछे चल रहे विभागों से देरी के कारण पूछे जाएंगे और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही वह भी परखा जाएगा कि योजनाओं के लिए मिले बजट का किताब उपयोग हुआ और निर्धारित लक्ष्य के मुकामले विभागों का प्रदर्शन कैसा रहा। इन योजनाओं पर रहेगा खास फोकस समीक्षा के दायरे में आयुधान भारत योजना, प्रधानमंत्री अन्नदास योजना, मुख्यमंत्री अवकाश योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री समृद्धिक विकास योजना और मुख्यमंत्री कृषि समुल्लेख योजना समेत कुल 37 महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा विभागवार विकास परियोजनाओं और लंबित कार्यों की भी समीक्षा होगी। शिकायत निस्तारण का भी मांग जाएगा हिस्सा डिप्टी सीएम कार्यालय में जनवरी 2026 से अब तक प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति भी बैठक का अग्र एजेंडा है। सभी विभागों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है कि कितनी शिकायतों का समय पर समाधान किया गया और कितने मामले अभी लंबित हैं। अधिकारियों को इस संबंध में भी जवाब देना होगा। लापरवाही मिलने पर हो सकती है कार्रवाई प्रशासनिक सुर्जों का कहना है कि समीक्षा के दौरान यदि किसी विभाग की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलती या शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारियों के प्रक्षेत्र कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। ऐसे में यह समीक्षा बैठक कई विभागों के लिए परीक्षा से कम नहीं मानी जा रही है।

शिक्षा नीति

हलांकि आजकल शिक्षा मंत्री धर्मेंद प्रधान के इन्तीफे पर विश्वास का जोर है, 'नीट' ऐर लोक में धोखी तो लेकर भी सरकार पर काफी दबाव है, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का शिक्षा संचालन आज भी विश्व विख्यात और सटीक व सस्ता है। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 'एनईपी 2020' प्रस्तुत की तब इसे ज्वित रूप से भारत की शिक्षा व्यवस्था में 34 वर्षों बाद किया गया पहला व्यापक सुधार बताया गया। उह वर्ष बाद यह नीति केवल एक दृष्टि या घोषणा भर नहीं रह गई है, बल्कि कार्यान्वयन के अस्थिक चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली चरण में प्रवेश कर चुकी है। दुह विस्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत के शिक्षा इंतहास के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है, क्योंकि यह एक नई सदी के लिए निर्मित शिक्षा नीति है। भारत की पिछली शिक्षा नीति वर्ष 1986 में बनाई गई थी और 1992 में उसमें संशोधन किया गया था। उस समय न इंटरनेट था, न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और न ही वे जस्माईखिकीय तथा आर्थिक चुनौतियां थी जो आज भारत के सामने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य इसी विस्मति को दूर करना था। इसने कठोर और सीमित शैक्षणिक संरचनाओं के स्थान पर बहुविषयक, लचीली और परिणामोन्मुख शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की। इहक दृष्टिकोण उच्च शिक्षा को केवल विशेषज्ञ तैयार करने वाली प्रणाली नहीं भासत बल्कि जीवन भर सीखने वाले, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ङाल सकने वाले नागरिकों के निर्माण का आहार मानती है। नार वर्षोंय सततक कार्यक्रम जिसमें अनेक प्रदेश और संस्थान विकस्य है, विषयगत सीमाओं को समाप्त करना तथा व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधार की शिक्षा से जोड़ना जैसे प्रावधान केवल सतहसे परिवर्तन नहीं हैं। वे इस बात की मूलभूत पुनर्कल्पना है कि ङिणी का अर्थ न्या है और विद्यार्थी की बौद्धिक यात्रा किस प्रकार संप्रिड होनी चाहिए। इन प्रावधानों के कार्यान्वयन ने देशभर के विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रमों, मूल्यकन प्रणालियों और शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को पुनर्ीड करने के लिए प्रेरित किया है। बहुविषयक शिक्षा के अघार पर विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर सबसे स्पष्ट परिवर्तन एकल विषयक ङर्ष से बाहर निकलना रहा है। जो संस्थान पहले विद्यार्थियों को केवल एक ही विषयधारा तक सीमित रखते थे, अब उन्हें विभिन्न विषयों में क्रेडिट आधारित वैकल्पिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने पड़ रहे हैं। इसी विज्ञान का विद्यार्थी लोक नीति का अध्ययन कर सकता है और मानविकी का विद्यार्थी डेटा विश्लेषण की समझ विकसित कर सकता है। यह केवल समय, सांीण का प्रश्न नहीं है, बल्कि संस्थागत रोन्त्र शिक्षक भर्ती और मूल्यकन प्रणालियों में व्यापक परिवर्तन की मांग करता है। नई शिक्षा नीति को सबसे महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं में से एक मानाया और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहन देना है, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर तथा धीरे-धीरे उच्च शिक्षा में भी। यह केवल भाषाई विरासत का सम्मान नहीं है, बल्कि शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने का व्यावहारिक उपाय है। भारत के अनेक विद्यार्थी अपनी क्षमता के कारण नहींए बल्कि भाषा संबंधी बाधाओं के कारण पीछे रह जाते हैं। इसलिए प्राथमिका आधारित शिक्षा ज्ञान तक पहुँच को अधिक लोकतांत्रिक बनाती है। देशी और स्वयं जैसे डिजिटल युवाओं का निर्माण करती रहे और उन्हे रोजगारपरक कौशल न प्रदान करे तो भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। इतने व्यापक स्तर के किसी भी सुधार के साथ चुनौतियां स्वाभाविक रूप से जुड़ी होती हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एवमेंस ङ्ग आयोजित परीक्षाओं, विशेषकर नीट, यूजी को लेकर ङल के वर्षों में बई प्रश्न उठे हैं। इन परिस्थितियों ने पाठशाला, जवाबदेही और परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है। हालांकि इन चुनौतियों को मानकीकृत मूल्यकन व्यवस्था को समाप्त करने के अघार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए। भारत के विश्वविद्यालय अनेक नियामक संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईटीई), फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अधीन कार्य करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इन विविध नियामकीय ङंठों को अधिक समन्वित और सुव्यवस्थित बनाने की परिकल्पना की है। जब तक यह पूर्णतः साकार नहीं होता, विश्वविद्यालयों को विभिन्न नियामकों को अपेक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति, विदेशी डिग्रीयों की मान्यता को सरल बनाना तथा अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षित करने की पहल इस नीति के प्रमुख आयाम हैं। इसका उद्देश्य भारत को केवल प्रतिभा निर्माक देश के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): हट गरीब क पक्का घर, सम्मानजनक जीवन की मजबूत नींव

एक सुरक्षित और सम्मानजनक आवास केवल चार दीवारों और ङल का नाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा, आत्मसम्मान और बेहतर भविष्य का आधार होता है। जब किसी परिवार को पक्का घर मिलता है तो उसके जीवन में केवल रहने की सुविधा नहीं बढ़ती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी खुलते हैं। इसी सोच को साकार करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण गरीबों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का मार्ग प्रसारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि

माननीय प्रधानमंत्री जी के "सबको पक्का मकान" के ऐतिहासिक संकल्प को धारतल पर उतारते हुए उत्तर प्रदेश ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' के सुदृढ़ क्रियान्वयन में देश भर में एक नया मानकड स्थापित किया है। प्रदेश सरकार की प्रभावी कार्यप्रणाली, जीरो-टॉलरेंस नीति और प्रधानमन्ीक पाठशाली व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य के लाखों बेघर और कच्चे मकानों में रह रहे ग्रामीण परिवारों को सुस्थित आशियाना सलभ हुआ है। यह योजना ग्रामीण भारत के बुनियादी ङर्षों को सुदृढ़ करने और 'अंत्योदय' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक युगांतकारी पाल साबित हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मूल उद्देश्य निर्धन एवं वंचित वर्ग को एक परिणामपूर्ण जीवन, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। प्रदेश सरकार की जन-कल्याणकारी नीतियों और पारदर्शी प्रशासनिक ढंग के चलते यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को ङंचा उठाने और आमजन के विश्वास को सुदृढ़ करने का प्रमुख माध्यम बन गई है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, प्रदेश सरकार ने आवासों का स्थायित्व महिलाओं को अत्यंत परिवार के साथ संयुक्त रूप से प्रदान करने की नीति अपनाई है। योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष प्रमाण अनेकों जनपद के विकास खंड अमेठी के अंतर्गत ग्राम पंचायत तिलेकपुर की निवासी दुर्गा देवी को मिला पक्का घर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सतक कदम है। सीमिता आय और बुनियादी सभ्नों के अभाव में दुर्गा देवी का परिवार दशकों से एक नजर कच्चे मकान में लगातार समस्याओं का सामना कर रहा था। बरसात के मौसम में घर की छत टपकने और दीवारों में नमी से परिवार की सुरक्षा पर खतरा बना रहता था। परिवार को भारी बारिश के दौरान घर में जलभरण का सामना करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त, भीषण गर्मी और कड़ुके की ठंड जैसी प्रतिकूल मौसमी स्थितियों से बचाव का कोई समुचित और सुस्थित साधन परिवार के पास उपलब्ध नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपने सीमित संसाधनों से एक पक्के आवास का निर्माण कर

सके। अभाव और अनिश्चितता के इस कठिन दौर में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उन्हें जीवन में एक सुरक्षा कवच और नई आशा बन्कर आई। इस योजना ने उनके जीवन को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान की दिशा में अग्रसर किया है। प्रदेश सरकार की स्पष्ट और पारदर्शी नीति के अनुकूल ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र लाभार्थियों के निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के तहत दुर्गा देवी को योजना में शामिल किया गया। जयन से लेकर स्वीकृति तक की

दुर्गा देवी को आवंटित आवास इसी महिला सशक्तिकरण नीति का जीवंत उदाहरण है, जिसने समाज में महिलाओं की निर्णय क्षमता और संपत्ति में उनके अधिकार को मजबूत किया है। अब दुर्गा देवी और उनका परिवार एक सुविधायुक्त, सुरक्षित और पक्के मकान में निह रहकर निवास कर रहा है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं से कच्चे मकान के क्षतिग्रस्त होने का भय अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। घर में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता से पारिवारिक माहौल में सकारात्मक बदलाव आया है और बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है। योजना की इस जमीनी सफलता के पीछे प्रदेश सरकार की स्पष्ट नीति और जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता एवं सतत कार्ययोजना की प्रमुख भूमिका रही है।

सके। अभाव और अनिश्चितता के इस कठिन दौर में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उन्हें जीवन में एक सुरक्षा कवच और नई आशा बन्कर आई। इस योजना ने उनके जीवन को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान की दिशा में अग्रसर किया है। प्रदेश सरकार की स्पष्ट और पारदर्शी नीति के अनुकूल ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र लाभार्थियों के निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के तहत दुर्गा देवी को योजना में शामिल किया गया। जयन से लेकर स्वीकृति तक की

विक्रम-1: नए भारत की अंतरिक्ष उड़ान का स्वर्णिम अध्याय

ललित गंग ।

भारत ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि यदि संकल्प, वैज्ञानिक दृष्टि और नवकार का संगम हो तो अकाश भी सीमा नहीं, बल्कि संभावनाओं का प्रारंभ बन जाता है। भारत के पहले निजी अर्धितरफैट 'विक्रम-1' का सफल प्रक्षेपण केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, नवचार आधारित अर्थव्यवस्था और विज्ञान-प्रधान भविष्य की ओर बढ़ते हुए का एक नया घोषणापत्र है। ब्रह्मरक्षेत्र के सरोजिध भवन अंतरिक्ष केंद्र से 'मिशन आगमन' के अंतर्गत हूँ यह ऐतिहासिक उड़ान भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि अब अंतरिक्ष विज्ञान केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि निजी उद्यम भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की अंतरिक्ष उड़ान का स्वर्णिम अध्याय एवं निजी अंतरिक्ष क्रांति की आकाशीय सफलताओं की नई जमीन है। विक्रम-1 की सफलता उस महान वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिन्होंने कभी कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष विज्ञान विनिर्दिष्ट नहीं, बल्कि विकास का अनिवार्य साधन है। आज उसी विचार की आधुनिक अभिव्यक्ति सहाईस्ट एगोरोपेस के रूप में दिखाई देती है, जिसने अपने पहले ही प्रयास में इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि केवल एक विजय है क्योंकि इस समय दुनिया में केवल कुछ ही देशों के निजी उद्यम अर्धितरफैट रैकेट विकसित कर पा रहे हैं। भारत अब इस विशेषता समूह में शामिल हो गया है, जहां नवचार, वैज्ञानिक कौशल और उद्यमशीलता मिलकर नई संभावनाओं का निर्माण कर रहे हैं। अमेरिका के स्पेसएक्स ने जिस निजी अंतरिक्ष क्रांति की शुरुआत की थी, भारत ने अब उसका अपना खदेरी रैकट प्रस्तुत कर दिया है। विक्रम-1 को तकनीकी विशेषज्ञता' भी इसे विशेष बनाती है। पूरी तरह कार्बन कंपोजिट से निर्मित यह रैकेट अपेक्षाकृत हल्का, अधिक मजबूत तथा कम लागत वाला है। थ्री-डी प्रिंटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग ने इसके निर्माण ङर्ष को उल्लेखनीय रूप से कम किया है। इसका सीधा अर्थ है कि भविष्य में छोटे उद्यमों के प्रक्षेपण का वैश्विक बाजार भारत के लिए नए आर्थिक अवसर लेकर

आएगा। आज दुनिया में संसार, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, रक्षा, आरंभ प्रबंधन, इंटरनेट सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों के लिए हजारों छोटे उद्यमों की आवश्यकता बढ़ रही है। ऐसे में भारत कम लागत और उच्च विश्वसनीयता के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। 'विक्रम-1' को विकसित करने वाली निजी कंपनियों 'सहाईस्ट एगोरोपेस' ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के नरक विक्रम साराभाई के नाम पर इस रैकेट का नामकरण कर न सिर्फ उन्हे सच्ची ब्रह्मज्ज्ञति अर्पित की है, बल्कि हमारे औद्योगिक घरानों को भी यह संदेश दिया है कि कार्परेट करते हुए भी अपने देश की समृद्ध विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए। गौर कीजिए, अर्धितरफैट विक्रम-1 ने जस भारत ने अपना पहला उरधक अंतरिक्ष में भेजा था, तब उसका नामकरण महान खगोल वैज्ञानिक अरीरधु के नाम पर किया गया था। यह सफलता केवल एक कंपनी को उपलब्ध नहीं है। यह उस नई नीति का परिणाम भी है जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश और स्टार्टअप के लिए खोलने का सार्वभौमिक फैसला किया। नई अंतरिक्ष नीति, इन-स्पेस जैसी संस्थाओं की स्थापना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदार प्रवधानों ने भारतीय युवाओं के सामने नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। आज देश में अनेक स्पेस स्टार्टअप उग्रह निर्माण, प्रक्षेपण प्रणाली, अंतरिक्ष सत्तार और डेटा सेकओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह फैसला भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगा। किन्तु हर सफलता अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती है। विक्रम-1 की पहली उड़ान सफल अवश्य रही है, परंतु अंतरिक्ष उद्योग में स्थायी सफलता केवल एक प्रक्षेपण से सुनिश्चित नहीं होती। सहाईस्ट एगोरोपेस को अब वैश्विक बाजार में स्पेसएक्स, रैकेट लेव तथा चीन की अरुन निजी कंपनियों जैसी सशक्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। निर्मित श्रद्धा, समय पर प्रक्षेपण, कम लागत, उच्च विश्वसनीयता तथा भविष्य में पुनः प्रयोज्य रैकेट तकनीक विकसित करना उसका अपनी बड़ी परीक्षा होगी। अंतरिक्ष उद्योग में विकास समझे बड़े पुनर्ी होता है और वह निरंतर गफल अभिधानों से ही अर्जित किया जा सकता है। इस ऐतिहासिक सफलता के बीच एक गंभीर प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा है-हमारे और निजी कंपनियों के बीच संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं प्राथम हों।

सिन्धु जल समझौता और पाक

'पाकिस्तान निम तमजे ये 1960 में हूँ भारत के साथ 'सिन्धु जल संधि' के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल करके भारतीय रुख के विकट नम्रत बनाने का अस्फल प्रयास कर रहा है हमसे यही सिद्ध होता है कि वह इस संधि की विभिन्न शर्तों की बदले पारिवर्णैव व मौसम मित्रान के अनुकूल समर्थक समीक्षा करने को तैयार नहीं है और यह मान कर चल रहा है कि 66 साल पहले जैसा मौसम का मित्रान हुआ करता था आज भी वैसा ही है। इसके साथ ही पाकिस्तान निम तम जल आर्कस्वद को अपने विदेश नीति का अंग बनाकर हुए है, विशेषकर भारत के विरुद्ध वह अपनी सीमा से दहशतगर्दी को भेज कर निम तम तह के कलहानत के कारणभर में रल्लिध है उसीमे दोनो देशों के आभासी समकष बेअसर रहेंगे? यही वजह है कि जब पिछले वर्ष अर्धितरफैट में कश्मीर के फलतगम से पाकिस्तान से आये आर्कस्वदोंमें ने 20 भारतीय पर्यटकों की निमम तथा को तो भारत सरकार ने जल संधि के अनुसार रखने की घोषणा की और कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर का आर्कस्वद नहीं छोड़ेगा तब तक उसके साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं होगी। साथ ही भारत की मोदी सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब वकत आ गया है कि सिन्धु जल संधि की शर्तों का पुनर्निर्धार किया जाना है। फलतगम में निम तम भारतीय पर्यटकों का मजबूत पुछ-पुछ कर उनका बेखुशी से काल किया गया था उसमे मान्यता भी चीत्तार का उठे थी। इस हत्यकांड का सम्पने स्वर से पुनरुत विशेष जम्मु-कश्मीर की मुफिस काल जन्म ने भी किया था और इसके श्रिंखला स्वरः स्पष्ट रूप से कई दिना के लिए विदेश नीति को बंद रखे था। वजहमें में 1960 में उत्तलीन प्रधानमन्त्री ख. पं. नव्जार लाल नेहरू ने बड़ दिल दिखाते हुए विश्व कैक की गल्लगयता में प्रिप्तनर 1960 में इस संधि पर कानूनी में इतहास क्रिये थे जबकि पाकिस्तान की तरफ इसके उत्तलीन राष्ट्रपति जनरल अयुब ने दासकत किये थे। इस संधि का मुल आधार आपसी विश्वास व सहैदत था जिसमे जल सीतो के अभाव कल देत पाकिस्तान के लोनों को सीतो व पाने का पानी उपलब्ध हो सके। इस समय तक भारत व पाकिस्तान के बीच कश्मीर संधि के अलावा कोई बड़ा युद्ध भी नहीं हुआ था अतः परिस्थिति पूर्णतः भिन्न थी। मगर इसके बाद 1965 व 1971 में दोनो देशों के बीच भीषण युद्ध हुए जिनमें पाकिस्तान ने मूह को खई मगर इसके बावजूद हमने सिन्धु जल समझौता जारी रखा। इसके बाद 1989 से पाकिस्तान ने भारत में आर्कस्वदों गतिविधियों को बढ़ाया और हजार नरम देश को नीति पर चलना शुरू किया और 1999 में कश्मीरल जैसल कल भी किया। मगर पाकिस्तान यही नहीं रुका इसने 2002 में भारतीय संसद पर हमले से लेखर 2008 में मुम्बई में ज्मम आर्कस्वदों छल्ला भी किया जिसमे 167 के करीब देशी-विदेशी नागरिक मारे गये। पाकिस्तान यही नहीं रुका, बल्कि वह लगातार भारत में आर्कस्वदों गतिविधियों को अंनम देत रहा और केमुदा नागरिकों को हत्या करता रहा। इसी क्रम में अपने पिछले मलत फलतगम में 20 भारतीय पर्यटकों की हत्या को जिसमे मोदी सरकार के सभ का बांध टूट गया और उसने जल संधि को मुलवी करने का फैसला कर लिया। अब पाकिस्तान इसके खिलाफ ही खे मजाता घुस रहा है। इस संधि की शर्तों के अनुसार सिन्धु नील जल प्रादा क्षेत्र को छह प्राकष नईवर्गों को दो श्रेणियों पूरे व परिसर में बांटा गया। इनमे से पूरे की तीन नईवर्ग ब्यार, रही व सलतुन के पाने पर भारत को अधिकार दिया गया जबकि परिसर की तीन नईवर्ग सिन्धु, चेनाब व इंदम के पानी पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया।

उपयोग भी किया जा रहा है। एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से निवधित निरीक्षण, सोशल ऑडिट, पात्रता सूची का सत्यापन तथा आवास प्लस सर्वे-2024 के जरिए पात्र लाभार्थियों की पहचान जैसी व्यवस्थाओं ने योजना को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है। वर्तमान में स्थायी पात्रता सूची के अंतिम सत्यापन हेतु ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए लगातार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। राजमिस्त्री प्रशिक्षण, निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका सोशल ऑडिट, निरीक्षण

प्रणाली, आवास पूर्णता और भूमिहीन लाभार्थियों की भूमि उपलब्ध कराने जैसे अनेक क्षेत्रों में प्रदेश आज देश में अग्रणी स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आज केवल आवास निर्माण की योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और समावेशी प्रगति का मजबूत आधार बन चुकी है। यह योजना लाखों परिवारों को जीवन में सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास का नया अध्याय लिख रही है। आने वाले वर्षों में यह अभियान प्रत्येक पात्र परिवार तक पक्का घर पहुंचाकर आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

'पीएम आवास के बाहर राहुल का धरना एक बचकानी राजनीति का नमूना', बीजेपी बोली- देश को बांटकर सत्ता में आना चाहते हैं

नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर अपने संवैधानिक पद से जुड़े विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और दावा किया कि कांग्रेस नेता देश को बांटकर सत्ता में आना चाहते हैं। भाजपा ने राहुल गांधी पर 'राष्ट्र-विरोधी तत्वों के साथ मिलीभगत' का भी आरोप लगाया और उनके प्रदर्शन को 'दिशाहीन' तथा 'बचकानी राजनीति' का उदाहरण बताया। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को 'नीट' परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था और प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग

की थी। बाद में पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वादा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार की 'राष्ट्र-विरोधी तत्वों के साथ मिलीभगत' है। उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, 'राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की जांच होनी चाहिए। सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि उन्होंने विदेश में किन लोगों से मुलाकात की, वह इस्लामी देशों के किन अधिकारियों से मिले, भारत को तोड़ने का प्रयास करने वाले किन लोगों से मिले, किन चीनी अधिकारियों से मिले और क्या उन्हें सोरोस फाउंडेशन से धन मिल रहा है ?' दुबे ने दावा किया कि



मंगलवार के प्रदर्शन के कारण उनका बेटा परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचा। उन्होंने कहा, 'मेरा बेटा प्रदर्शन के कारण परीक्षा केंद्र देर से पहुंचा। क्या किसी नेता का बेटा होना अपराध है? क्या वह छात्र नहीं है? क्या वह परीक्षार्थी नहीं है?' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास

कर रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए देश को बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा 'राहुल गांधी आज वह करने के लिए प्रयासरत हैं जो उनकी दादी ने आपातकाल के दौरान किया था कि मीडिया को क्या कहना चाहिए और क्या प्रकाशित करना चाहिए। वह देश को बांट कर सत्ता में आना चाहते हैं।' भाजपा सांसद और पार्टी की

राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिले विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर उनका प्रदर्शन 'हताशा', 'निराशा' और 'बचकानी राजनीति' को दर्शाता है। राठौड़ ने कहा, 'नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने उनका दुरुपयोग किया। प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने का क्या औचित्य था? यह उनकी हताशा और निराशा की परकाष्ठ है। यह दिशाहीन और बचकानी राजनीति है।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने अपना रुख बदल लिया। राठौड़ ने कहा, 'पहले उन्होंने कहा कि यदि संसद में चर्चा होगी तो प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। जब सरकार चर्चा के लिए

तैयार हो गई तो उन्होंने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। किसी के इस्तीफे की मांग करना कोई मजाक नहीं है। राहुल गांधी गंभीर नहीं हैं।' उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता बुधवार दोपहर दो बजे से प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस नेतृत्व को 'सद्बुद्धि' देने की प्रार्थना करेंगे। भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह 'नीट' प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है और 'नीट' की पुनर्परीक्षा निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से कराई गई। सिन्हा ने 'इंडिया' गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन में एकजुटता का अभाव है और उसके घटक दल केवल अपने हितों की रक्षा के लिए साथ आए हैं।

दिल्ली मेट्रो के स्टेशन बंद किए जाने पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'बेहतर होगा कि...'



नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (22 जुलाई) को कहा कि युवा प्रदर्शनकारी विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, भले ही सभी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाएं। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में उन्होंने कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने की आलोचना की। केजरीवाल ने कहा, 'मेट्रो स्टेशन बंद करना गलत है। सरकार छात्रों और प्रदर्शनकारियों को जितना रोकने की कोशिश करेगी, आंदोलन उतना ही बढ़ेगा। अगर आप सभी मेट्रो स्टेशन बंद भी कर दें, तो भी वे

पैदल चले जाएंगे। ये युवा हैं। बेहतर होगा कि सरकार इन युवा प्रदर्शनकारियों की बात सुने। 'केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों को पूरा करने के बजाय उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, 'इन युवा प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश न करें। वे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का रास्ता निकाल ही लेंगे। 'बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने बुधवार सुबह सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, आईटीओ और खान

मार्केट समेत 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस आंदोलन का समर्थन करती है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से भी इसमें शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा, 'सभी को इसमें शामिल होना चाहिए। हम आंदोलन के समर्थन में जंतर-मंतर गए थे। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और परीक्षा प्रणाली विफल हो रही है। 'केजरीवाल ने कहा, 'शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? मंत्रियों को तो हमेशा बदला जाता है। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त किया जाना चाहिए। हम इस आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। ' इसके साथ ही उन्होंने निहत्थे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज सरकार द्वारा किए गए आतंकवाद के समान है।

राहुल गांधी बाले - 'प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगें', प्रदर्शन को दिया समर्थन



नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों के समर्थन में केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। राहुल गांधी ने 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा- सवाल यह है कि यह क्यों हुआ? इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के सामने तीन मांगें रखी हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हम छात्रों के आंदोलन का पूरा समर्थन कर रहे हैं। हम इसका पूरा

समर्थन कर रहे हैं... इस चर्चा में जितेंद्र सिंह की कोई जरूरत नहीं है। वह एक गैर-जरूरी व्यक्ति हैं। वह जो चाहें कह सकते हैं। वह इस चर्चा का एक गैर-जरूरी हिस्सा हैं। चर्चा बहुत सीधी-सी है। छात्रों की मांगें साफ हैं। पहली मांग है कि धर्मद प्रधान को हटाया जाए। दूसरी मांग है कि जिन लोगों ने छात्रों के साथ मारपीट की, उन्हें सजा दी जाए। तीसरी मांग है कि प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगें। जितेंद्र सिंह जो भी कल्पना करना चाहते हैं, करें। उन्हें ऐसा करने की पूरी छूट है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने साथ हुई पुलिसिया कार्रवाई पर राहुल गांधी ने कहा, मैं इन सब का आदी हूँ। मेरा काम देश

के लोगों की इच्छा को सामने रखने का है। विपक्ष के नेता के तौर पर। यह बहुत ही छोटी कीमत है, यह बड़ी बात नहीं है। मैंने यह ऐसा यह मेरे लिए गर्व की बात है। धरने के दौरान दो पंच लगे वह बड़ी बात नहीं है। राहुल ने कहा, जितना पैसा भारत सरकार शिक्षा बजट पर खर्च करती है, नीट एजाम पर भी उतना ही पैसा खर्च होता है, जो भारतीय परिवार देते हैं। सरकार साल भर टैक्स लेती है, इसी एजुकेशन बजट के लिए। धर्मद प्रधान ने देश की शिक्षा व्यवस्था नष्ट कर दी है। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह एजुकेशन दे, नौकरियां दे, बेहतर भविष्य दे। उन्होंने कहा कि, कोई व्यक्ति या लोगों का एक समूह हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। भारत की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसकी शिक्षा व्यवस्था और उसके छात्र हैं, लेकिन उनके भविष्य को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, सरकार क्या कर रही है? एक भी दोषीसिद्ध (कॉक्करोच) नहीं हुई है। यही पहला और पूरी तरह से जायज कारण है कि हमारे युवा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की, बोले- देश को आपकी जरूरत



नई दिल्ली । जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन के बीच सीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अपना अनशन समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का जीवन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी सेहत को देखते हुए अब उन्हें भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनशन खत्म होने का मतलब आंदोलन का खत्म होना नहीं होगा। दीपके ने कहा कि जब तक उनकी मुख्य मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सोनम वांगचुक के अनशन का 25वां दिन है और बिना भोजन के इतने लंबे समय तक रहने से उनके जीवन पर गंभीर खतरा है। उन्होंने

कहा, 'देश को उनकी जरूरत है। मैं उनसे अनशन खत्म करने की अपील करता हूँ। लेकिन हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती।' उन्होंने कहा कि यदि सोनम वांगचुक अनशन समाप्त भी कर देते हैं, तब भी प्रदर्शन जारी रहेगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। दीपके ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और किसी भी ऐसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी जिससे आंदोलन या देश की छवि को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन महत्वा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर के बताए अहिंसक रास्ते पर चलेगा। उन्होंने समर्थकों से भी अपील की कि वे संयम बनाए रखें और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखें। उनके अनुसार आंदोलन का उद्देश्य केवल जवाबदेही तय कराना है।

सीजेपी प्रवक्ता अशुतोष रांका बोले - 20 जुलाई सिर्फ ट्रेलर... अगर सरकार छात्रों की नहीं मानी तो...

नई दिल्ली । कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि अशुतोष रांका ने बुधवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर वह चल रहे प्रोटेस्ट की मांगों को पूरा करने में नाकाम रही तो देश के युवा उन्हें 'बहुत बुरी तरह हरा देंगे। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई का प्रदर्शन सिर्फ एक 'ट्रेलर' था। रांका ने कहा कि चल रहा प्रोटेस्ट 'इंडिया का सबसे बड़ा मूवमेंट' है 'आजादी के बाद के इतिहास' और चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो लाखों और लोग दिल्ली आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत के आजादी के बाद के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है...हमने यह बहुत साफ कहा है: 20 तारीख को जो हुआ वह एक ट्रेलर था। अगर सरकार नहीं मानती है, तो लाखों और लोग दिल्ली आएंगे क्योंकि इस बार

हम पीछे नहीं हटेंगे और चुप नहीं रहेंगे...सरकार को सच में ठेक से काम करने की जरूरत है; नहीं तो, इस देश के युवा उन्हें बहुत बुरी तरह हरा देंगे। रांका ने इस दावे को खारिज करते हुए कि प्रदर्शनकारी 'शांतिपूर्ण' नहीं थे, रांका ने कहा कि 20 जुलाई का मार्च शांतिपूर्ण था और आरोप लगाया कि पुलिस के स्टूडेंट्स पर बल प्रयोग करने के बाद ही अफरा-तफरी मची। उन्होंने कहा कि सरकार एक कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम शांतिपूर्ण नहीं रहेंगे, लेकिन हम हैं। 20 तारीख का मार्च भी शांतिपूर्ण था लेकिन अफरा-तफरी सिर्फ उस जगह पर हुई जहां पुलिस ने बेरहमी दिखाई और स्टूडेंट्स को पीटा। उन्होंने कहा, 'युवा 31 दिनों से यहां शांति से बैठे हैं क्योंकि हम गांधी और अंबेडकर के सिद्धांतों को

मानते हैं। रांका ने यह भी कहा कि वे भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होने देंगे, और कहा कि इस तरह के आशवासन के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा, 'हमने एक बहुत साफ मांग रखी है और अभिजीत दीपके ने इसके बारे में बात की थी। हम किसी भी तरह की FIR नहीं करेंगे या भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होने देंगे; इसके बिना विरोध खत्म नहीं होगा। रांका ने कहा, 'जहां तक हमारी टीम की लीडरशिप की बात है, हम किसी भी FIR से नहीं डरते, हम पहले दिन से ही UAPA और NSA के तहत गिरफ्तार होने को तैयार हैं। हमारी लड़ाई के लिए जेल एक छोटी सी कीमत है। आंदोलन के समर्थन में राजनीतिक पार्टियों से एक साथ आने की अपील करते हुए, रांका

ने कहा कि प्रदर्शनकारी भारतीय जनता पार्टी सहित किसी भी पार्टी के सदस्यों का स्वागत करेंगे। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, भले ही वे बीजेपी के लोग हों, उन्हें एक साथ आना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत बड़ा आंदोलन है और मांग सच्ची है।' उन्होंने कहा, 'हम उन सभी का स्वागत करते हैं। इस बीच, विपक्षी एमपी बुधवार को संसद के मकर द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। विरोध प्रदर्शन का समय टेटेविल्ली सुबह 10:30 बजे तय किया गया है, जिस दौरान विपक्षी विधायक नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों पर भी चिंता जताएंगे। वे 20 जुलाई को छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करेंगे।

'न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 61 वर्ष करने पर करें विचार'

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने को कहा। अदालत ने यह निर्देश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें देशभर के जिला न्यायापालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति बी. मोहन की पीठ ने कहा, 'सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के उच्च न्यायालयों से परामर्श कर इस मुद्दे पर फैसला लें। अगर वे सहमत होते हैं तो ऐसे राज्यों में न्यायिक अधिकारियों को 61 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, यह व्यवस्था इस मामले के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। 'पीठ ने कहा कि यह व्यवस्था एक अप्रैल, 2026 से लागू होगी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अंतरिम व्यवस्था इस कानूनी प्रश्न पर अंतिम सुनवाई को प्रभावित नहीं करेगी कि क्या पूरे देश में जिला न्यायापालिका के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की जानी चाहिए। अदालत ने कहा, 'हम स्पष्ट करते हैं कि शुरुआत में तय किए गए कानूनी प्रश्न पर यह अदालत स्वतंत्र रूप से फैसला करेगी।

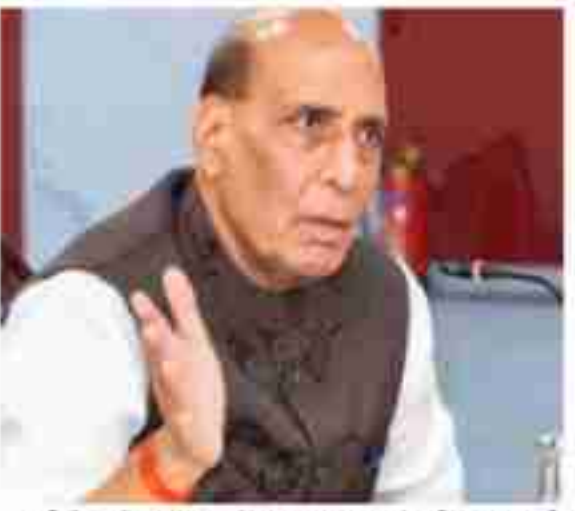
राज्यसभा में खड़गे बोले- प्रधान इस्तीफा दें, फिर चर्चा करेंगे



हंगामे के बीच दोनों सदन गुरुवार तक स्थगित

नई दिल्ली । संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को विपक्ष ने केंद्रीय जनता पार्टी के समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के बीच लोकसभा-राज्यसभा को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में गोल्लूकान्तेन खड़गे ने कहा कि, वे सदन में नोट पेश

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला: बोले- छात्रों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा, संसद में करें चर्चा



नई दिल्ली । संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को विपक्ष ने केंद्रीय जनता पार्टी के समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के बीच लोकसभा-राज्यसभा को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में गोल्लूकान्तेन खड़गे ने कहा कि, वे सदन में नोट पेश

इसे छात्रों को भटकाने का एक असफल प्रयास कर दिया। राजनाथ सिंह ने विज्ञापन बताया कि भारत का समृद्धिदाय युवा इन सभी कोविडों को अच्छी तरह समझता है और वह विकास तथा राष्ट्र निर्माण का रास्ता ही चुनेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार छात्रों और युवाओं को आकाशवाणी को पूरा करने तथा उनके कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील है और वह सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ, खासकर छात्रों के साथ कोई अन्याय न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के कुछ नेता जनता के बीच बहाने की गुस्ता पीय करने की कोशिश कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके बजाय विपक्ष संसद के बजट सत्रों पर समाधान खोजने का अनुरोध प्रथम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष वास्तव में गंभीर है, तो उसे सत्र में हंगामा करने के बजाय सदन के भीतर मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।

अनंतनाग में आतंकी हमला!: पुलिस दल पर फायरिंग, गोली लगने से हेड कांस्टेबल आशीक हुसैन बलिदान



श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस दल पर हुए हमले में घायल हेड कांस्टेबल आशीक हुसैन की इलाज के दौरान बलिदान। अधिकारियों के अनुसार, कोरुनगम रोड इलाके में पुलिस ठेकाने पर अज्ञात बंदूकधारी ने हमला किया था। हमले के दौरान कई गोलियों की आवाज सुनी गई। इस गोलीबारी में पुलिस हेड कांस्टेबल आशीक हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया।

दिया। एक बॉम्ब पुलिस अधिकारी ने घटना को पुष्टि करते हुए बताया कि हमले के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सुरक्षाबलों ने हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षाबल असुरक्षित के क्षेत्रों में सतर्कता गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और हमलावरों की पहचान व निराकरण के लिए अभियान जारी है। आतंकी संगठन द रॉजेंट्स फ्रंट ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। सुरक्षा एजेंसियां घटना की जांच कर रही हैं और हमलावरों तक पहुंचने के लिए सभी संभावित सुगम जुटाए जा रहे हैं।

दिल्ली की तरह पटना में उग्र प्रदर्शन, छात्रों ने पुलिस-मीडिया पर चलाए रोड़े; सीएम आवास के पास लाठीचार्ज

पटना । पटना में बाइपल की छत्र संघटन- अल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बुधवार को बड़ा हंगामा किया। दिल्ली की तरह पटना में भीड़ जुटकर हंगामा किया। प्रदर्शन के नाम पर जुटी भीड़ को निरीक्षित करने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया। करतब कर रहे पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। भीड़ इस हद तक उग्र थी कि अमृत गैस, चाट केन जैसे डेनगनाम केका गए। भीड़ तिरस्कारित होती और एकजुट हो जाती। गांधी मैदान के पास जय प्रकाश नारायण गैलरी पर रोड़भर शुरू हुआ और जयजयका-जयजयका होते हुए बेली रोड होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गया। यहाँ तक हंगामा होता रहा। डिप्टी सीएम विनय कुमार चौधरी के आवास में सीएम सभट चौधरी आवास जाने के दायज्ज लतरेजवाक तक हुआ। पटना पुलिस से मागता नहीं सोंफता तो केंद्रीय बली



को सड़क पर जताए गया। प्रदर्शन की जगह छोड़ शहर को किया प्रभावित पटना में गंदीनाग थाने के पास प्रदर्शन को जगह तय है, लेकिन हर तरफ से जुटी हुई भीड़ सबसे फले गांधी मैदान के पास जेपी गैलरी पर पहुंची। यहाँ प्रदर्शन करतु हुए, छुट्ट के बैर तले सभी छात्र जयजयका चौवाहे की ओर निकलने लगे। राज्यभवन की ओर बढ़ते की कोरिश के दौरान पटना पुलिस को टीम में

छत्रबंगला चौवाहे पर बैरिस्टींग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। पटना एसएसपी ने यहाँ पर पचास सख्खा में पुलिस बल को तैनात कर दी। चाट केन लेकर पुलिस जवान तैनात थे। यहाँ प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से नोकझोंक पर उतर आए। पटना आईनी की एक्काई गार्डी पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी रैलीबाजी करते लगे। पुलिस के साथ मौखिया को भी

निशाना बनाया। पटना आईनी ने शांति व्यवस्था भंग करने वाले प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। विधानसभा की सुरक्षा बढ़ी हलात पर कानू पाने के लिए पुलिस ने अमृत गैस के गोल छेड़े और चाट केन से पानी की नौछर कर प्रदर्शनकारियों को तिरस्कारित करने की कोशिश की। मौके पर भारी सख्खा में पुलिस बल तैनात किया, लेकिन टुकड़ों में बंटकर यह प्रदर्शनकारी कैली रोड पर विधानसभा अग्रहा के अग्रिम के बगल से छिप्टी सीएस अग्रिम तक पहुंच गए। यहाँ से लोक भवन जाने के रास्ते पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर डूने हिरासत में लेना शुरू किया। इसी हलत को देखते हुए विधानसभा के पास भी सुरक्षा मुस्तौद रखी गई है और निपाककों को सदन के अंदर हो रखा गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को कहा, छात्रों पर लाठीचार्ज मामले पर केंद्र को नोटिस



नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर हुई घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और दृश्य संरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की गई है। यह याचिका कार्यकारी सीएम वांगचुक की भुल हड़ताल के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को चुनौती देती है। इसमें छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई का निष्कर्ष है। याचिका में 18 जुलाई को हुए अभियान की निष्पत्ती जांच की गई है। साथ ही, सन्तुष्टी को सुरक्षित रखने और शांतिपूर्ण विरोध के सांख्यिक आधिकार की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश बनाने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिकारता एन. हरिहरन, विकास मिश्र और गोपाल शंकर-नारायणन ने अदालत में बहस की। उन्होंने बताया कि छात्र हृद्यध्वज परेखा से संबंधित अपनी शिकायतों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए थे। यह प्रदर्शन लगभग 20 दिनों से चल रहा था और इस दौरान कोई हिंस नहीं हुई थी। अधिकारताओं ने अदालत को बताया कि पुलिस ने बिना चेतावनी दिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इसमें से कुछ लाठीचार्ज में कोलें लगी हुई थी। पुलिस ने फ्लेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन और टेनर का भी प्रयोग किया। पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप अधिकारताओं ने अदालत को बताया कि महिलाओं के साथ बदसलूकी और निजी अंगों पर हमले के आरोप भी लगाए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारता विकास सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस के जवानों की वृत्ति पर नाम पड़ना नहीं लगी थी। इसमें उनकी पहचान छिपाई जा रही थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से घटना के दृश्य देखने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ताओं ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और दृश्य सामग्री संरक्षित करने की मांग की है। इसके साथ ही, एक स्वतंत्र एसआईटी जांच कराने की भी मांग की गई है। उन्होंने बताया कि इस घटना में 90 से अधिक छात्र घायल हुए हैं। अदालत ने दृश्य देखने का आश्वासन दिया है और मामले की सुनवाई जारी है।

की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिकारता एन. हरिहरन, विकास मिश्र और गोपाल शंकर-नारायणन ने अदालत में बहस की। उन्होंने बताया कि छात्र हृद्यध्वज परेखा से संबंधित अपनी शिकायतों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए थे। यह प्रदर्शन लगभग 20 दिनों से चल रहा था और इस दौरान कोई हिंस नहीं हुई थी। अधिकारताओं ने अदालत को बताया कि पुलिस ने बिना चेतावनी दिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इसमें से कुछ लाठीचार्ज में कोलें लगी हुई थी। पुलिस ने फ्लेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन और टेनर का भी प्रयोग किया। पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप अधिकारताओं ने अदालत को बताया कि महिलाओं के साथ बदसलूकी और निजी अंगों पर हमले के आरोप भी लगाए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारता विकास सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस के जवानों की वृत्ति पर नाम पड़ना नहीं लगी थी। इसमें उनकी पहचान छिपाई जा रही थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से घटना के दृश्य देखने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ताओं ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और दृश्य सामग्री संरक्षित करने की मांग की है। इसके साथ ही, एक स्वतंत्र एसआईटी जांच कराने की भी मांग की गई है। उन्होंने बताया कि इस घटना में 90 से अधिक छात्र घायल हुए हैं। अदालत ने दृश्य देखने का आश्वासन दिया है और मामले की सुनवाई जारी है।

'अदालत का समय बर्बाद न करें'- पुलिस कार्रवाई के खिलाफ तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनाकार

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में कांक्रोन जनता पार्टी (कांजपा) के नेतृत्व में निकाले गए मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से बुधवार को इनाकार कर दिया और प्रधान न्यायाधीश (सोनेआई) सुर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि अदालत का समय बर्बाद न करें। प्रधान न्यायाधीश (सोनेआई) सुर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जयमालया बगवती और न्यायमूर्ति वी. गोहना की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया। वीडियो देखने के इच्छुक नहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश कर्कोल ने कहा, " पुलिस को बर्बाद से जुड़े वीडियो भी मैं पास है... यदि इस मामले को काल (बहुमतिवार) सूचीबद्ध किया जा सके...।" उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ पुलिस ने कथित तौर पर बर्बरता की और याचिका में तीन अनुरोध किए गए हैं। प्रधान न्यायाधीश ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध ठुकराते हुए स्पष्ट किया कि पीठ इस स्तर पर वीडियो देखने की इच्छुक नहीं है। सोनेआई बोले 'हमारा समय बर्बाद मत कीजिए' उन्होंने कहा, "हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है... हम वीडियो नहीं देखना चाहते।" कर्कोल के छात्रों की पीछे की बात दोबारा कहने और वीडियो को हवाला देने पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते।" यह याचिका संभवतः को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कांक्रोन जनता पार्टी (कांजपा) के संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई से संबंधित है।

भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा भारतीय संस्कृति, समरसता और सेवा का जीवंत प्रतीक: मुख्यमंत्री

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नाथ सिंह रैनी ने पंजाब के राजपुरा में आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में की शिरकत

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नाथ सिंह रैनी ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता, सेवा और मानवता के कल्याण का जीवंत संदेश है। यह यात्रा नरेंद्र प्रेम, सेवा, समानता और राष्ट्र एकता का मार्ग दिखाती है तथा समाज को जोड़ने का कार्य करती है। मुख्यमंत्री श्री



नाथ सिंह रैनी आन पंजाब के राजपुरा में आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में चतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और ब्रह्मालुओं को बर्बाद व शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींची और झाड़ू लगाकर उपस्थितगण को स्वच्छता अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ,



बलभद्र जी तथा माता सुभद्रा के चरणों में शीश नवाते हुए कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ सम्पूर्ण मानवता के नाथ हैं। उनके दरबार में किसी प्रकार का ऊँच-नीच, जाति, वर्ग अथवा अंगीरे-गरीबी का भेद नहीं होता। रथ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ईश्वर के समक्ष सभी समान हैं और प्रेम, सेवा तथा समर्पण ही सच्ची भक्ति का आधार है।



इस यात्रा में हजारों लोग मिलकर रथ की रस्सी खींचते हैं, जहां किसी की जाति, भाषा अथवा सामाजिक स्थिति नहीं पूछी जाती। यही हमारा सनातन संस्कृति और 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की विरासत का गौरवशाली प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति संदेव 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का संदेश देती आई है। आज जब विश्व विभाजन, हिंसा और संघर्ष जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रेम, सेवा, भाईचारे और एकता का संदेश देकर पूरी मानवता को नई दिशा प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इकॉन संस्था के सेवा कार्य की सराहना करते हुए कहा कि संस्था पिछले दो दशकों से सरकार, गैरमेवा, गीता प्रचार, अन्नदान, युवा जागरण और मानव सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन का अभियान चला रही है। उन्होंने सभी स्वयंसेवकों को इस महान कार्य के लिए बधाई दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री असीम गोवंत सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राहुल बोले-पुलिसवालों ने मेरे कान में कहा सरकार को हटाइए: मुझे घसीटा तो मुंह से खून आया, दो-तीन पंच लगे, लेकिन धर्मेन्द्र प्रधान को जाना होगा

नई दिल्ली । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल नई दिल्ली स्थित कांक्रिम मुख्यालय इंदिरा भवन में प्रेम कार्यक्रम की। संबोधन से पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो चलाया। उसमें पुलिस छात्रों पर लाठी चार्ज कर रही थी। इसके बाद उन्होंने सरकार को घेरना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कई घवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र केवल एक निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, जो उनका अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई छात्र लगातार तनाव झेल रहे हैं और पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण कुछ छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली। उनके अनुसार छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कभी दुनिया की सबसे बेहतर व्यवस्थाओं में गिनी जाती थी, लेकिन अब यह पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 152 बार पररगव लीक हुए हैं, यानी औसतन हर महीने एक पेपर लीक हुआ। उन्होंने कहा कि हर बार लाखों छात्रों को फिर से परीक्षा की तैयारी करना पड़ती है और उन्हें दोबारा उसी मानसिक दबाव से गुजरना पड़ता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की इस परेशानी को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि करीब 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार इन घटनाओं से प्रभावित हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की है। राहुल गांधी की तीन प्रमुख मांगें क्या? 'धर्मेन्द्र प्रधान को पद से हटाय जाए'- राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अपने दायित्व निभाने में विफल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए उन्हें पद से हटाना जाना चाहिए। 'छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने वालों की जयजयकारें तय हों...' राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर कार्रवाई का आदेश देने वाले और उसे लागू करने वाले सभी लोगों की जयजयकारें तय की जानी चाहिए। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। 'सरकार छात्रों से माफी मांगे...' राहुल गांधी ने कहा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए अधिकार सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने मांग की कि छात्रों के साथ जो हुआ, उसके लिए सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उससे माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने पेपर लीक



और सजा को लेकर क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक को घटनाएं सामने आने के बावजूद एक भी मामले में किसी को भी एक सजा नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग या संगठन समूह देश की शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था देश की सबसे बड़ी पूंजी है और यदि यहाँ व्यवस्था कमजोर होगी तो विकास और देश के भविष्य पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा लगातार टूट रहा है, क्योंकि हर पेपर लीक के बाद उन्हें फिर से शुरूआत करनी पड़ती है। शिक्षा की लागत को लेकर राहुल गांधी ने क्या दावा किया?

राहुल गांधी ने कहा कि समस्या केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा अब आम परिवारों के लिए बहुत महंगी भी हो गई है। उन्होंने दावा किया कि हर साल केवल नोट परीक्षा की तैयारी और उससे जुड़े खर्च पर परिवार लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये खर्च करते हैं। वहीं, केंद्र सरकार का शिक्षा बजट लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि दोनों रकम

राहुल गांधी ने कहा कि समस्या केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा अब आम परिवारों के लिए बहुत महंगी भी हो गई है। उन्होंने दावा किया कि हर साल केवल नोट परीक्षा की तैयारी और उससे जुड़े खर्च पर परिवार लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये खर्च करते हैं। वहीं, केंद्र सरकार का शिक्षा बजट लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि दोनों रकम

लगभग बराबर है। राहुल गांधी के अनुसार इसका मतलब यह है कि परिवार अपने बच्चों की शिक्षा पर लगभग उतना ही खर्च कर रहे हैं, जितना सरकार पूरे देश को शिक्षा पर करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले परिवारों से इतना पैसा खर्च करना जाता है और बाद में पेपर लीक होने से उनकी मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद हो जाते हैं। राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा कि आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। उन्होंने कहा कि छात्र पढ़ते-पढ़ते डीनटर, कर्कोल या अन्य परेशान बन जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके लिए रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि निर्माण क्षेत्र कमजोर हो चुका है और बजट में अधिकतर चीजें उत्तर दिखाई देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नए उद्यमियों को बैंकों से पैसे वितरित सख्तता नहीं मिलती, क्योंकि अधिकारी उन्हें कुछ बड़ी कंपनियों को चला जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि बुद्धिमान और आर्टिटी क्षेत्र में कल्याण के कारण कॉर्पोरेट नौकरियां प्रभावित हो रही हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण भी हो रहा है। ऐसे में युवाओं के पास सरकारी नौकरी ही प्रमुख विकल्प बचता है, लेकिन उस भी कठिन और महंगी बना दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांक्रिम छात्रों की भावनाओं और उनकी

मांगों के साथ पूरी तरह खड़ी है। उन्होंने कहा कि जो भी छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, उनकी जिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हाल के दिनों में छात्रों के साथ जो हुआ, उसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। छात्रों के प्रदर्शन और सरकार को लेकर क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि छात्र सड़कों पर किसी राजनीतिक कारण

से नहीं, बल्कि अपने भविष्य की चिंता में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग सिर्फ इतनी है कि उन्हें निष्पक्ष और भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था मिले। उन्होंने सवाल किया कि अधिकार छात्रों ने ऐसा क्या गलत किया है कि उनके सामने सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र केवल अपने अधिकार की बात कर रहे हैं और सरकार को उनकी आवाज सुनी चाहिए। उनके अनुसार जब तक पेपर लीक पर सजा कार्रवाई, दोषियों को सजा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, तब तक छात्रों का आक्रोश कम नहीं होगा।



सक्षम भारत की बेवसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।